



## 8 मार्च-अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को गांव-गांव में जोश-खरोश के साथ मनाएंगे! महिलाओं, खासकर अल्पसंख्यक महिलाओं पर बढ़ते ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी हमलों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे!

प्यारी महिलाओं!

8 मार्च- एक ऐतिहासिक दिन है. श्रमिक महिलाओं ने अपने जुझारू संघर्ष के जरिए उस दिन को ऐतिहासिक बनाया. हालांकि पूंजीवादी समाज ने अपने फायदे के लिए महिलाओं को सामंती बंधनों से मुक्त कर सामाजिक उत्पादन में शामिल किया. लेकिन उसने पुरुषों की तुलना में महिलाओं की मेहनत को और अधिक लूटा था. इस लूट के खिलाफ महिलाएं आंदोलनरत हो गईं. 8 मार्च, 1908 को अमेरिका के न्यूयार्क शहर में कपड़े सीलने वाली श्रमिक महिलाओं ने कार्यस्थलों की बुरी परिस्थितियों को सुधारने, कामकाज के घंटों को कम करने, महिलाओं को समान अधिकार और मतदान के अधिकार उपलब्ध कराने और बाल श्रमिक व्यवस्था को खतम करने आदि मांगों को लेकर एक ऐतिहासिक संघर्ष किया. यह संघर्ष वहीं थम नहीं गया. इसके बाद भी काम के घंटों को कम करने, वेतन बढ़ाने, मताधिकार उपलब्ध कराने आदि मांगों को लेकर कई सिलाई कारखानों की श्रमिक महिलाएं हड़ताल करने लगी थीं. संघर्षों के इस सिलसिले को जारी रखते हुए 22 नवंबर, 1909 से 20 हजार महिलाओं के साथ एक लंबी हड़ताल जारी रही थी. बर्कली सदी में 13 हफ्तों तक हड़ताल जारी रखने वाली इन महिलाओं ने इस अवधारणा कि महिलाएं लंबी व कठिन हड़ताल नहीं कर सकती हैं, को तोड़ दिया था. इस दौरान महिलाओं ने हर दिन पुलिस लाठियों की मार खायी थी. गिरफ्तारियों व जेल की सजाओं का सामना किया था.

अमेरिकी महिलाओं द्वारा संचालित इन संघर्षों के सिलसिले ने दुनिया के कई देशों की जनता व क्रांतिकारियों को प्रभावित किया. जर्मन कम्युनिस्ट नेत्री कामरेड क्लारा जेटकिन इन संघर्षों का जोरदार स्वागत किया. उनकी ही पहलकदमी से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का निर्णय 1910 में कोपेनहेगन में आयोजित समाजवादी महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किया गया. बाद में संपन्न समाजवादी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इस निर्णय का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया. इस निर्णय के पक्ष में मतदान करने वालों में रूसी क्रांति के महान नायक कामरेड लेनिन भी थे.

इसके बाद 1911 से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर में, संघर्षरत महिलाओं द्वारा आयोजित किया जा रहा है. न सिर्फ रूस व चीन की क्रांतियों के दौरान बल्कि दोनों देशों में क्रांति सफल होने के बाद भी, जब तक ये दोनों देश समाजवादी रास्ते पर आगे बढ़ते रहे थे, 8 मार्च - अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को एक बड़े ही प्रेरणा दिवस के रूप में जोश-खरोश के साथ मनाया जाता था. हमारे देश में क्रांतिकारी पार्टियों के नेतृत्व में 80 के दशक से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है.

सीपीआई (माओवादी) की केंद्रीय कमेटी द्वारा कई सालों से 8-मार्च के मौके पर महिलाओं को किसी ज्वलंत मुद्दे के खिलाफ संघर्षरत होने का आह्वान किया जा रहा है. इसी तरह इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं, खासकर अल्पसंख्यक महिलाओं पर ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादियों के हमलों के खिलाफ जुझारू व संगठित रूप में लड़ने का आह्वान दिया गया.

हालांकि संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा गया है, लेकिन व्यवहार में ऐसा कभी नहीं है. कांग्रेस जो 1947 के बाद अधिकतर वर्ष केंद्र में सत्तारूढ़ थी, के कार्यकाल में हिंदू धर्म का दबदबा जारी रहा था. मुसलमान, ईसाई, सिख आदि अल्पसंख्यकों पर भेदभाव जारी रहा, वे हाशियों पर ही थे.

2002 में गुजरात में हजारों मुसलमानों के नरसंहार का नेतृत्व करने वाले मोदी की अगुआई में केंद्र में 2014 में जब से ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादियों का शासन शुरू हुआ, तब से हालत बद से बदतर हो गई. हमारे देश को सौ प्रतिशत हिंदू राज्य बनाने के संघ परिवार के एजेंडे को आगे ले जाने के फिरेक में देश में असहिष्णुता बढ़ायी जा रही है. घरवापसी, लव जिहाद, गोसंरक्षण आदि नामों पर दलितों, आदिवासियों व अल्पसंख्यकों पर भीड़ द्वारा जानलेवा हमलों को अंजाम दिया जा रहा है. केंद्र में मोदी के सत्तारूढ़ होने के बाद अब तक भीड़ द्वारा 400 से ज्यादा हत्याएं की गई हैं.

कई महिलाएं भी हिंदुत्व फासीवादियों का शिकार हो रही हैं. देश में जारी असहिष्णु माहौल के खिलाफ आवाज उठाने वाली प्रगतिशील महिलाओं को हिंदू कट्टरपंथी लोग अपना निशाना बना रहे हैं. इन फासीवादियों द्वारा प्रगतिशील लेखिका व संपादिका गौरी लंकेश की हत्या की गई. भीमा-कोरेगांव में हिंसा को प्रेरित करने का आरोप लगाते हुए अन्य प्रगतिशील व क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों के साथ शोमा सेन एवं सुधा भरद्वाज को गिरफ्तार किया गया. 1 जनवरी, 2018 को भगवा आतंकियों द्वारा भीमा-कोरेगांव में किए गए उत्पात की चश्मदीद 19 वर्षीय दलित युवती की हत्या की गई. अरुंधती रॉय, कविता कृष्णण आदि प्रगतिशील बुद्धिजीवियों को डराया धमकाया जा रहा है. अखिल भारतीय मराठा सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देने के लिए आह्वानित की गई नयनातारा सेहगल को आखिरी वक्त में अपमानजनक तरीके से इसलिए रोक दिया गया कि वे देश में फैलाए जा रहे भगवा आतंक के खिलाफ बोलने जा रही थी. इस तरह महिला बुद्धिजीवियों की अभिव्यक्ति की आजादी पर हमलें किए जा रहे हैं.

कठुआ व उन्नाव बलात्कार कांडों के दौरान भी हिंदुत्व फासीवादियों की घिनौनी हरकतें सामने आईं. कश्मीर में कठुआ में आठ वर्षीय कश्मीरी बच्ची के साथ किए गए अत्याचार व उसकी हत्या के मामले में अपराधी भाजपाइयों को बचाने के लिए भाजपा के तत्कालीन दो मंत्रियों के अलावा संघ परिवार के बहुत सारे लोग बेशर्मी से आगे आए. उतना ही नहीं पीड़िता के पक्ष में खड़ी होनी वाली वकील दीपिका सिंह पर अत्याचार करने की धमकियां इन ताकतों द्वारा दी गईं. इस अत्याचार के खिलाफ सोशल मीडिया में कार्टून पोस्ट करने वाली स्वाति वड्लामूडी को जान से मारने की धमकी दी गई. उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक अवयस्क बालिका के साथ भाजपा के एक विधायक ने बलात्कार किया, तो पीड़िता की शिकायत के बावजूद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की. उल्टे में न सिर्फ पीड़िता के पिता की गिरफ्तारी की गई बल्कि हिरासत में उनकी हत्या भी की गई.

शबरिमलाई मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की इजाजत देते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले के खिलाफ हिंदुत्व कट्टरपंथियों द्वारा हिंसक प्रदर्शन किए गए. मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करने वाली कई महिलाओं पर जानलेवा हमलें किए गए.

पूर्वोत्तर व कश्मीर जनता की आजादी की आकांक्षाओं को लौह बूटों से कुचल दिया जा रहा है. 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हुए जबर्दस्त हमले के बाद न सिर्फ कश्मीर बल्कि देश भर में कश्मीरी जनता पर बड़े पैमाने पर हिंसा जारी है. सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा कश्मीरी मांओं पर अपने बेटों का आत्मसमर्पण करवाने का दबाव डाला जा रहा है. कई राज्यों द्वारा, विद्यालयों द्वारा कश्मीरी छात्राओं व छात्रों को पढ़ाई छोड़ कर जाने के

आदेश दिए गए. हिंदू धर्मांधता व छद्म देशभक्ति से भड़कायी गई भीड़ से बचाने के लिए अपने-आपको लंबे समय तक कमरे में बंद करने में कश्मीरी छात्राएं मजबूर हो गईं. कश्मीर में तैनात सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा वहां की महिलाओं पर अकथनीय अत्याचार जारी हैं. पुलवामा घटना के बाद फिर से भेजे गए सौ से अधिक कंपनियों के सशस्त्र बलों से वहां की महिलाओं की सुरक्षा और खतरे में पड़ गई.

महिलाओं पर भौतिक हमलों के अलावा कई विश्वविद्यालयों में ड्रेस कोड के रूप में उन पर पाबंदियां लागू की जा रही हैं. 'राष्ट्रीय सेविका समिति', 'किशोरी वर्ग', 'आरोग्य भारती' आदि आरएसएस की अनुषंगिक संस्थाओं के जरिए ब्राह्मणीय विचारधारा के अनुरूप महिलाओं को ढालने की कोशिश की जा रही है.

छत्तीसगढ़ में विगत 15 वर्षों के भाजपा के कार्यकाल में यहां के आदिवासियों पर हिंदू धर्म को थोपने के लिए साजिशाना कोशिशों की गई थीं. रामकृष्ण मिशन, वनवासी कल्याण आश्रम, सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या भारती, एकलव्य स्कूल आदि द्वारा आदिवासी अस्तित्व व अस्मिता पर लगातार चोट पहुंचाया जा रहा है. घरवापसी के नाम पर आदिवासियों को जबरन हिंदू धर्म में धकेल दिया जा रहा है. सोशल मीडिया में आदिवासियों, दलितों व मुसलमानों के खिलाफ उनकी देवी-देवताओं के खिलाफ, उनके रहन-सहन, खान-पान, पहनावे-ओढ़ावे की आदतों पर अभद्र, अश्लील टिप्पणियां की गईं. पाठ्य पुस्तकों में आदिवासी व महिला विरोधी अवधारणाओं को जोड़ने की कोशिश की गई.

शोषण व उत्पीड़न के खिलाफ विगत 37 वर्षों से सीपीआई (माओवादी) के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जारी जनयुद्ध व जनसंघर्ष इस भगवा आतंकवाद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. इस जनयुद्ध व जनसंघर्ष में यहां की महिलाओं की अहम भागीदारी है. न सिर्फ भगवा आतंकवाद बल्कि उसे संरक्षण देने वाले लुटेरे शासक वर्गों के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बन गए क्रांतिकारी आंदोलन पर विगत के भाजपा कार्यकाल में बड़े पैमाने पर दमन जारी था. इस दमन में विशेष रूप से महिलाओं को केंद्रित किया गया. उनके साथ मार-पीट, अश्लील हरकतें और बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और उनकी गिरफ्तारियां व हत्याएं बेरोकटोक जारी रही थीं. इस भीषण दमन के खिलाफ अवाज उठाने वाली महिलाओं को ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी सरकारों और उनके सशस्त्र बलों ने अपना निशाना बना दिया. बेला भाटिया, शालिनी गेरा, ईशा खडेलवाल, मालिनी सुब्रह्मण्यम, नंदिनी सुंदर, सोनी सोडी आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों व पत्रकारों को जानलेवा हमलों, धमकियों, गिरफ्तारियों, अपमानों का सामना करना पड़ा.

महिलाओं पर अत्याचारों को राज्य हिंसा का अभिन्न व मुख्य हिस्सा बनाया गया है. देश खासकर दंडकारण्य के संघर्षरत इलाकों में महिलाओं पर अनगिनत, अकथनीय अत्याचार लगातार जारी हैं.

भाजपा सरकार द्वारा महिलाओं व जनता पर जारी हमलों के विरोध में अवाज उठाते हुए जनता को दिग्भ्रमित करते हुए अपने वोट बैंक को बढ़ा कर

➤ 8 मार्च - अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिंदाबाद!

➤ ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवाद को परास्त करेंगे! महिलाओं खासकर धार्मिक अल्पसंख्यक महिलाओं के अधिकारों को ऊंचा उठाएंगे!

➤ जनता पर जारी युद्ध 'समाधान' को हराने जन संघर्षों व जनयुद्ध को तेज व व्यापक बनाएंगे!

बूपेश बघेल के नेतृत्व में सत्तारूढ़ हुई कांग्रेस सरकार भी अब विगत की भाजपा सरकार के नक्शेकदम ही चलते हुए जनता पर युद्ध को जारी रखी हुई है. शपथ ग्रहण के समय से लेकर ही जनता, पीएलजीए, पार्टी पर हमलें बेरोकटोक जारी हैं. इन हमलों के दौरान महिलाओं को निशाना बनाने के ताजा उदाहरण भी हमारे सामने हैं. 2 फरवरी को सुकमा जिले के गोडेलगुड़ा गांव के पास लकड़ी लाने गई तीन ग्रामीण महिलाओं के ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी करने की वजह से एक महिला - सुक्की पोडियाम की मौत हुई और एक महिला - कलमू देवे घायल हुई. माड़ डिविजन के इंद्रावती एरिया के ताडबल्ला गांव के पास मिलिशिया के ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी करके 10 लोगों की हत्या की. इनमें तीन अवयस्क बालिकाओं सहित पांच लड़कियां - विज्जे माडवी (20), सुदरी ओयम (18), पालो ओडी (17), रेयो परसा (15) और शांति आरकी (12) - थीं. दरअसल ये लड़कियां घायल अवस्था में पुलिस बलों के हाथ लग गई थीं. फायरिंग आवाज सुन कर घटना स्थल पहुंची महिलाओं ने उन्हें नहीं मारने का आग्रह किया था. इसके बावजूद मांओं की आंखों के सामने ही उन बेटियों के साथ अत्याचार कर उनकी बेरहमी से यातनाएं दे कर, हत्या की गई. पुलिस वालों के इस क्रूर नरसंहार की निंदा करते हुए लगभग 5000 लोग जिनमें महिलाओं की तादाद अधिक थी, पुलिस बलों का पीछा करते हुए पहले भैरमगढ़ फिर वहां से बीजापुर गए. पुलिस बलों द्वारा हथियारों को तान कर डरा-धमकाने के बावजूद उन्होंने पुलिस बलों का पीछा नहीं छोड़ा. वे पुलिस बलों के साथ संघर्ष करके सभी शहीदों की लाशें लाए.

वर्तमान में दंडकारण्य में जारी क्रांतिकारी संघर्ष में महिलाओं की बड़ी ही भूमिका है. पेशेवर क्रांतिकारियों के तौर पर पार्टी, पार्टी के विभिन्न विभागों, पीएलजीए, क्रांतिकारी जनताना सरकारों व जन संगठनों में उनका महत्वपूर्ण योगदान है. अंशकालीन रूप में भी पार्टी, मिलिशिया, क्रांतिकारी जनताना सरकारों व जन संगठनों में महिलाएं सक्रिय भूमिका निभा रही हैं. गांवों पर पुलिस हमलों का प्रतिरोध करने में, पुलिस के हाथों से अपनों को छुड़ाने में, झूठी मुठभेड़ों व मुठभेड़ों के मृतकों की लाशें लाने में महिलाओं की भागीदारी दिन-ब-दिन बढ़ रही है. जनयुद्ध व जन संघर्ष में महिलाओं की भागीदारी ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादियों जो महिलाओं को चार दीवारों के बीच में ही रखना चाहते हैं, को फूटी आंख नहीं सुहाता है. इसलिए दुश्मन बल महिलाओं को विशेष रूप से निशाना बना रहे हैं. खास कर महिलाओं के खिलाफ यौन अत्याचारों को एक मजबूत दमनकारी हथियार बना दिया गया. साधारण ग्रामीण महिलाओं, निहत्थे कार्यकर्ताओं, घायल अवस्था में अपने हाथ लग गयी सशस्त्र महिला कामरेडों के साथ भी धिनौने तरीके से सरकारी बलों द्वारा अत्याचार किए जा रहे हैं.

महिलाओं पर बेरोकटोक जारी ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी हमलों और राज्यहिंसा को रोकने का एक ही मार्ग है, जनयुद्ध-जनसंघर्ष को आगे बढ़ाना. 8 मार्च - अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सगर्व विरासत को आगे बढ़ाते हुए जनयुद्ध-जनसंघर्षों में महिलाओं को अपनी भागीदारी को और बढ़ानी चाहिए.

क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ,

उत्तर सब जोनल ब्यूरो,

दंडकारण्य,

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी).